

प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

सचिव
कृषि
उत्तराखण्ड शासन।

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभाग

देहरादून:

दिनांक : 17 मई, 2010

महोदय,

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में संशोधन करते हुए लघु एवं सीमान्त कृषकों के स्वामित्व की भूमि पर सिंचाई सुविधाओं के विकास, उद्यानीकरण, वृक्षारोपण तथा भूमि विकास के कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत अनुमन्य किये गये हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार के राजपत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है (इसका अंग्रेजी रूप ही पढ़ा जाये)।

सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिकता से प्रदेश के समस्त अटल आदर्श ग्राम के रूप में अभिज्ञानित ग्रामों तथा पायलट परियोजना के रूप में जनपद पौड़ी के विकासखण्ड पोखड़ा एवं यमकेश्वर, जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर तथा जनपद नैनीताल के विकासखण्ड कोटाबाग में अनुसूचित जाति/जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा धारित भूमि पर उक्त संदर्भित कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कराये जाएं।

पायलट परियोजना के रूप में चयनित विकासखण्डों के प्रत्येक न्याय पंचायत तथा अटल आदर्श ग्रामों में एक साथ कम से कम 200 नाली भूमि का चयन अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि को प्राथमिकता देते हुए कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा। परियोजना में चयनित ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण एवं नियोजन का कार्य कृषि विभाग के सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। परियोजनाओं का आगणन कार्य विशेष के अनुसार संबंधित विभाग की अनुमोदित दरों के अनुरूप होगा। सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन द्वारा तैयार किये गये ग्रामवार परियोजना सक्षम अधिकारी से तकनीकी अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी को प्रस्तुत किये जाएंगे,

जिसे संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित शासन में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु धनराशि परियोजना स्वीकृति के पश्चात् संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। इन कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन कृषि विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के विकासखण्ड स्तरीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा भी उक्त परियोजनाओं का random आधार पर स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।

कृपया पायलट परियोजना के रूप में चयनित विकासखण्डों तथा अटल आदर्श ग्रामों में सर्वेक्षण, नियोजन एवं परियोजना स्वीकृति का कार्य प्रत्येक दशा में 30 जून 2010 तक पूर्ण किया जाय तथा इस योजना से मार्च 2011 तक आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाय। उक्त परियोजनाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देशानुसार संचालित की जाएंगी।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्या 38/8-2/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2010-11 तददिनांकित:-

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
2. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड।
3. अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. राज्य एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(सुभाष कुमार)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1158]

No. 1158]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2009

का.आ. 1824(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अहित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का उपबंध।”

[फा. सं. जे-11013/2/2008-एनआईजेए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 में संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किए गए :

1. का. आ. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007
2. का. आ. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
3. का. आ. 2999(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2008

2725 GI/2009

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2009

S.O. 1824(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments in the Schedule I to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, paragraph 1, for sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

“(iv) provision of irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Schedule Castes and Schedule Tribes or below poverty line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008.”

[F.No. J-11013/2/2008-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note : Schedule I of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended vide following Notification Numbers :

1. S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007
2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008
3. S.O. 2999(E), dated the 31st December, 2008